

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-3

देहरादून : दिनांक 01 मई, 2017

विषय— महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों को उच्चिकृत/संशोधित वेतनमान का लाभ अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-130/महा0अधि0/2016, दिनांक 22 अगस्त, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड महाधिवक्ता कार्यालय के अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों की उत्तराखण्ड सचिवालय के अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों के वेतनमानों से समकक्षता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को अनुमन्य हो रहे विशेष भत्तों में से रू0 600 के अंश को ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए संशोधित वेतन बैंड रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 5400 का लाभ दिनांक 25 जुलाई, 2012 से एवं समीक्षा अधिकारियों को वेतनमान रू0.9300-34800, ग्रेड वेतन रू0.4200 के स्थान पर संशोधित ग्रेड वेतन रू0.4600 का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन उच्चिकृत/संशोधित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— शासनादेश के निर्गमन के पूर्व माह तक का 'एरियर' आयकर काटने के बाद जी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा और जिनका जी0पी0एफ0 खाता नहीं है उन्हें इसका भुगतान नकद किया जायेगा।

3— उक्तानुसार वेतनमानों के पुनरीक्षण/उच्चिकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-83/XXVII(7)/2017, दिनांक 27 अप्रैल, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- ०२ / (1) / xxxvi(3)/2017-389 / 2007-T.C., तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4- वित्त अनुभाग-5 / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रीतेश कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।